POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2014/अंक 07

कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 जुलाई, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-13

# ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जुलाई, 2014 मूल्य 50 पैसे

## आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! मुझे ही नहीं पूरे देश को नई सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से। क्योंकि, उन्होंने देशवासियों से 'अच्छे दिन' का वादा किया है। हमें दुनिया का सबसे बड़ा, गतिशील, ऊर्जा से भरपूर लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। मेरा मानना है जनता ने इस बार के चुनावों में इसे और मजबूत बनाया है।

हाल ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के बाद संसद में मोदी ने अपने वादों को दुहराते हुए सपनों को हकीकत में बदलने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। देश से गरीबी मिटाना और गांवों के विकास को पहली तवज्जह देने के साथ ही वादों को पूरा करने के तरीकों पर उन्होंने प्रकाश डाला वह उनके आत्मविश्वास व नेतृत्व क्षमता को परिभाषित करता है। उन्होंने श्रममेव जयते के उद्घोष के साथ देश की छवि को श्रेष्ठ भारत के रूप में बदलने, विकास के नये आयाम स्थापित करने का भरोसा भी दिया है।

महत्वपूर्ण यह भी है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के कलंक से सदन के दोनों सदनों को मुक्त करने, लोकतंत्र के लिए आलोचना को जरूरी करार देने और राज्यों में विकास की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने जैसे मुद्दे उनकी राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाते हैं।

देश के विकास के लिए एक बार फिर जनआंदोलन खड़ा कर छोटी-छोटी प्राथमिकताओं को पूरा करने, महंगाई को काबू में लाने, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, भ्रष्टाचार खत्म करने जैसे कई वादों को दुहराते हुए उन्होंने जो जिम्मेदारियां बताई हैं उनसे तो लगता है कि वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन कब तक, यह अभी कहना मुश्किल है...!

## बेरोजगार नहीं उठा पा रहे बेरोजगारी भत्ते का लाभ

*मिलता है 500 से 600 रुपए प्रति माह*

*श्रम व नियोजन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक स्नातक बेरोजगार को पांच सौ रुपए तथा निशक्त बेरोजगार को छह सौ रुपए मासिक भत्ता दिया जाता है। आवेदन के साथ ही योग्यता के दस्तावेज सहित आवेदक के बैंक अकाउंट नंबर लिया जाता है जिसमें भत्ता स्वीकृत होने पर हर माह राशि भेजी जाती है।*

राज्य में बेरोजगारी भत्ते के नियम सरल किए जाने के बावजूद अभी तक करीब 53 हजार स्नातक बेरोजगार ही यह भत्ता पा रहे हैं। जबकि प्रदेश में ऐसे बेरोजगारों की संख्या लाखों में है। श्रम व नियोजन विभाग की ओर से योजनाओं की जानकारी नहीं दिए जाने से बेरोजगार युवा लाभ नही उठा पा रहे हैं।

राज्य में बेरोजगारी भत्ते के नियमों का सरलीकरण एक अगस्त 2013 को किया गया था। नये नियमों के तहत स्नातक बेरोजगार के परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपए से कम है तो वह भत्ते के लिए जिला रोजगार कार्यालय में आवेदन करने का हकदार बन जाता है। विभाग की ओर से प्रचार-प्रसार नहीं किए जाने से योजना के दायरे में आने वाले स्नातक लाभ नहीं ले पा रहे हैं। विभाग के मुताबिक मार्च 2014 तक प्रदेश भर में सात लाख से भी ज्यादा युवा बेरोजगार हैं।

## दावा तो किया था, फिर भी नहीं चमके दांत!

जोधपुर निवासी 72 वर्षीय रामकृष्ण ने एक नामी टूथपेस्ट कम्पनी के खिलाफ उपभोक्ता मंच में परिवाद दायर किया। उन्होंने अपने परिवाद में बताया कि चौदह दिन तक दो बार ब्रश करने के बावजूद उनके दांत पीले ही रहे। जबकि कम्पनी का दावा था कि टूथपेस्ट से ब्रश करने पर उनके दांत सफेद हो जाएंगे और चमकने लगेंगे। उन्होंने कम्पनी के विज्ञापन को आम उपभोक्ता को भ्रमित करने वाला बताया।

मामले की सुनवाई पर कम्पनी की ओर से कहा गया कि यह चाइना में हुए रिसर्च वर्क का परिणाम था। कम्पनी की ओर से यह भी दलील दी गई कि दवा व चाय से जो दांत पीले हो जाते हैं वह कई बार सफेद नहीं होते हैं। लेकिन मंच ने कम्पनी के विज्ञापन को भ्रामक माना और उपभोक्ता को पांच हजार रुपए की क्षतिपूर्ति सहित टूथपेस्ट की कीमत लौटाने का आदेश दिया। जिला मंच ने कम्पनी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी मानते हुए 50 हजार रुपए का जुर्माना जमा कराने के आदेश भी दिए थे।

इस आदेश के खिलाफ कम्पनी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दर्ज कराई। लेकिन आयोग ने जिला मंच के फैसले को बरकरार रखा। इसके अलावा आयोग ने कम्पनी को दस हजार रुपए अलग से उपभोक्ता रामकृष्ण व्यास को अदा करने के आदेश भी दिए हैं।

## बजट ऐसा हो जो महंगाई रोके

राज्य का बजट ऐसा हो जिससे महंगाई पर लगाम लग सके। इसके लिए बजट में मूल्य निगरानी और नियंत्रण आयोग बनाने की घोषणा की जाए।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा प्रदेश के आगामी बजट के लिए सभी वर्गों से विचार-विमर्श हेतु आयोजित बैठक में प्रदेश के गैर सरकारी, सामाजिक और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों ने यह मांग उठाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखेगी। मद्देनजर बजट पर सभी से विचार-विमर्श की पहल की गई है। सरकार योजनाओं को स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से लागू करना चाहती है।

मुख्यमंत्री की इस पहल को अच्छा कदम बताते हुए संस्था प्रतिनिधियों ने कहा कि सभी विभागों से भी कहा जाए कि वे इसी तरह हर माह आम जनता से जुड़े संगठनों से विचार-विमर्श करें और उनके सुझावों पर गौर किया जाए। उन्होंने बैठक में प्रदेश में उपभोक्ता नीति लागू करने, उपभोक्ता कल्याण कोष का सही इस्तेमाल करने, उपभोक्ता मामलात विभाग को मजबूती देने, विभिन्न सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने, स्कूली शिक्षा में सुधार को अहमियत देने और महिला सशक्तिकरण के लिए कदम बढ़ाने के बारे में कई सुझाव भी सामने रखे।

## उजाले की खरीद में अंधेरगर्दी

पंचायती राज विभाग की ओर से गांवों में रोशनी करवाने के नाम पर लगवाई कई सोलर लाइटों की खरीद में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। मामला जयपुर जिले की चाकसू पंचायत समिति के वर्ष 2011 से 2013 की ऑडिट में पहली बार पकड़ में आया।

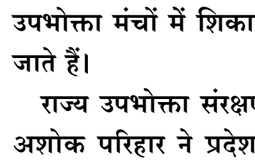


इसके बाद कई जिलों की पंचायतों में भी गड़बड़ी का खुलासा हुआ। पंचायत समितियों में बीडीओ तथा ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच व ग्राम सेवकों द्वारा बरती गई इस अंधेरगर्दी से सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा है। अब विभाग के आला अफसरों में हड़कंप मचा है।

लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट द्वारा की गई जांच में सामने आया है कि जो लाइट 21 हजार रुपए में खरीदी जानी थी, उसकी कीमत 28 हजार, 33 हजार और 49 हजार रुपए तक चुका दी गई। इतना ही नहीं सरकारी खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाने की बाद्धता होने के बावजूद कई पंचायतों में सिर्फ बातचीत के आधार पर और मौखिक आदेश से ऊंची दरों पर लाइटों की खरीद कर ली गई।

## उपभोक्ता संरक्षण में प्रदेश अव्वल

देश में उपभोक्ता की शिकायतों का समाधान करने में राजस्थान पहले नम्बर पर है, लेकिन जागरूकता कम होने से पढ़े-लिखे लोग भी उपभोक्ता मंचों में शिकायत करने से पीछे हट जाते हैं।

राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अशोक परिहार ने प्रदेश के जिला उपभोक्ता मंचों के अध्यक्षों और सदस्यों के वार्षिक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए यह विचार रखे।

उन्होंने कहा अगर जागरूकता होती तो आम आदमी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लेता। इस मौके पर गंगानगर, चूरू, टोंक, जयपुर-चतुर्थ और जोधपुर-द्वितीय जिला मंचों के अध्यक्षों व सदस्यों द्वारा किए गए बेहतर कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया।

## पंचायतों के बढ़ेंगे वित्तीय अधिकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गुलाबचन्द कटारिया ने बताया है ग्राम पंचायतों को दो लाख 50 हजार रुपए तक के कार्यों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करने की शक्ति दी जाएगी। अभी तक ग्राम पंचायत के पास एक लाख रुपए तक की ही शक्ति है।

इसी प्रकार पंचायत समिति की शक्ति 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तथा जिला परिषद की 10 लाख से 20 लाख रुपए की जाएगी। राज्य सरकार ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त स्टाफ, फंड और तकनीकी मदद उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है।

## गांवों में खुलेंगे मिनी बैंक

सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया है कि सरकार जल्द ही सहकारिता क्षेत्र में साढ़े तीन सौ मिनी बैंक खोलेगी। इन्हें अभी राजीव गांधी केन्द्रों में चलाया जाएगा। मिनी बैंकों को कम्प्यूटरीकृत भी किया जाएगा।

यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले बैंक संबंधी काम करेंगे। सरकार चाहती है कि मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी का भुगतान भी इन्हीं बैंकों के माध्यम से किया जाए, ताकि ग्रामीणों को मजदूरी समय पर मिल सके।

उन्होंने बताया कि सहकारिता क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू की जाएगी, जो ग्रामीणों को काफी फायदा पहुंचाने वाली होंगी।

## मंत्रियों को बतानी होगी संपत्ति

नरेन्द्र मोदी सरकार के सभी मंत्रियों को अपनी संपत्ति, देनदारी व व्यावसायिक हित का ब्योरा 31 जुलाई के पहले देना होगा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नए मंत्रियों के लिए आचार संहिता जारी की गई है। इसके मुताबिक जो मंत्री सरकार में आने से पहले किसी कारोबार के प्रबंधन या ऑपरेशन से जुड़े थे, वे उससे अपने संबंध खत्म कर लें। आचार संहिता पर अमल की निगरानी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद करेंगे।

मंत्रियों से कहा गया है वे प्रशासनिक अधिकारियों की राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखें। उन्हें उनके दायित्वों व जिम्मेदारियों के प्रतिकूल कोई काम करने को नहीं कहा जाए। मंत्री के परिजन न तो कोई ऐसा कारोबार करें, न ही ऐसे कारोबार में भागीदारी करें जो सरकार की सेवा या सामान की आपूर्ति करता हो।

## अन्ना बोले... अच्छे दिन आने वाले है

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ की और कहा कि केन्द्र में नई सरकार ने भविष्य के लिए आशाजनक तस्वीर सामने रखी है। इससे लग रहा है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं।

उन्होंने कहा कि नई सरकार के कामों पर नजर रखी जाएगी, अगर नई सरकार ने किए वादे नहीं निभाए तो आन्दोलन भी किया जाएगा।

## आएगा काला धन वापस!

केन्द्र में सत्ता संभालते ही नरेन्द्र मोदी सरकार ने पहला फैसला करते हुए विदेशों में जमा काले धन का पता लगाने के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति एस.बी. शाह की अध्यक्षता में ग्यारह सदस्यों की जांच टीम ने काम भी शुरू कर दिया है।

विदेशों में जमा काला धन देश में आने से हमारी अर्थव्यवस्था का कायापलट हो सकता है। इस पर टैक्स वसूली से जहां सरकारी आय में इजाफा होगा वहीं इस धन का उपयोग देश के विकास में हो सकेगा। जाने क्यों पिछली सरकार इस धन को वापस लाने में निष्क्रियता बरत रही थी। काले धन को लेकर नई सरकार का यह निर्णय देश के लिए एक सकारात्मक कदम सिद्ध होगा।

-जमनादास सिन्धी, अजमेर

## मनरेगा के तहत होगा पौधरोपण

प्रदेश में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सरकारी भवनों में पौधरोपण कराएगी। मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर करीब एक लाख सरकारी भवनों में पौधे लगाए जाएंगे। संबंधित ग्राम पंचायत को पांच वर्षों तक इन पौधों की देखभाल करनी होगी।

इसके लिए ग्राम पंचायतों को अपने स्तर पर अलग से प्रावधान कर इस योजना को वार्षिक कार्ययोजना में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान में उन्हीं भवनों को शामिल किया जाएगा जिनमें चारदिवारी बनी हुई हो, जिससे जानवर इन पौधों को नुकसान न पहुंचाएं।

## हर ग्राम पंचायत में होगा तालाब

राज्य सरकार परम्परागत जल स्त्रोतों को उपयोगी बनाने के लिए हर ग्राम पंचायत में एक तालाब को मॉडल बनाएगी। इस क्षेत्र में काम करने वाली पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ग्राम पंचायत में जल स्त्रोत के रूप में मौजूदा जलाशय, तालाब, तलाई व नाड़ी आदि जिन पर गांव के लोग और उनके मवेशी निर्भर हैं, उन्हें उपयोगी बनाया जाएगा।

इन्हें दीर्घायु बनाने एवं इनका सौन्दर्यीकरण करने के लिए ठोस कार्रवाई की जरूरत है। इसके लिए जिला कलेक्टरों को ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पत्र लिखा गया है कि हर गांव में एक मॉडल तालाब विकसित किया जाए। मनरेगा योजना के तहत इस कार्य को किया जा सकेगा।

## हर खेत का बनेगा मृदा कार्ड

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के हर खेत का मृदा स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए। खेत की तासीर के अनुरूप ही खाद-पानी डालकर बुवाई होनी चाहिए, जिससे किसान बेहतर पैदावार ले सकें। कृषि विभाग पहली प्राथमिकता के साथ इसके लिए अभियान चलाए।


## उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

जागो ग्राहक जागो

'कट्स' सेंटर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (कट्स कार्ट) द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण करने, शिकायतों से संबंधित सूचना एवं सलाह सेवाएं देने के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया हुआ है। कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत या समस्याओं के बारे में स्वयं व्यक्तिश कार्यालय समय में डी-218, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर स्थित कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है अथवा नीचे लिखे फोन, फैक्स व ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रेषित कर सकता है।

30 1983 2012 CUTS International

फोन: 141-2282823, 2282482, 5133259, फैक्स: 141-4015395
ईमेल: cart@cuts.org, वेबसाइट: www.cuts-international.org/cart

कट्स कार्ट


कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485